RJPP, Vol. 15, No. 2, 2017, ISSN (P) : 0976-3635, (e) :2454-3411, Impact Factor 4.0000 (ICRJIFR)
UGC Approved Journal No. 43279

उत्तर प्रदेश की राजनीतिक विचारधारा : एक मूल्यांकन

डॉ० सुधीर मलिक
पोस्ट डोक्टरल फैलो०, राजनीतिक विज्ञान विभाग, चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

सारांश

भारत एक गाँवों का देश है भारत की अधिकांश जनसंख्या गाँवों मे निवास करती है और आज भी भारतीय संस्कृति के विभिन्न रूप परम्परागत स्वरूप में गाँवों में दिखाई पड़ते है आज भी गाँवो में जाति, सम्प्रदाय एवं भूमि और राजनीति मुद्दे जवलंत है। भारतीय स्वतन्त्रा आन्दोलन में भी गाँवों के लोगों ने मुख्य भूमिका निभायी है वर्तमान भारत की राजनैतिक शक्ति और सत्ता का केन्द्र भी गाँव ही बन गये है गाँव मैं आज हमारी संस्कृति की परम्परागत स्वरूप विद्यमान है जो भारतीय वर्तमान राजनीति की रूपरेखा, प्रवृत्तियो को निर्धारण भी करता है अतः इस प्रकार गाँवो को पूर्णरूपेन राजनीतिक शक्ति का मूल स्रोत माना जा सकता है।

शोधपत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैः

डॉ० सुधीर मलिक, ''उत्तर प्रदेश की राजनीतिक विचारधारा : एक मूल्यांकन'', RJPP 2017, Vol. 15, No.2, pp. 105-110
http://anubooks.com/?page_id=2004
Artcile No. 15(RP564)

प्रस्तावना

भारत की अधिकांष जनसंख्या गाँवों में निवास करने के कारण विकास प्रक्रिया भी उससे अधूरी नही है जब तक गाँवों का सम्पूर्ण विकास नही होगा तब तक सम्पूर्ण भारत का विकास भी सम्भव नही है व ग्रामीण विकास अभी भी प्रारम्भिक अवस्था में ही है भारतीय लोकतन्त्र ने आजादी के इतने सालो बाद भी कृशक व उपाजित वर्गो इतनी उन्नति नही कर पाये है। समाज में हाशिये पर जीने वालो के अधिकारो के प्रति सरकारे कितनी सक्षम है आज भी जमीन से जुड़े लोगों (कृषक मजदूर आदिवासी) के जीवन स्तर में कितना परिवर्तन आया है वैश्वीकरण ने इनकी आजीविका को बुरी तरह प्रभावित किया है। इन तमाम सवालों के जवाब खोजना वर्तमान सन्दर्भ में प्रासिंगक होगा।

1887 की क्रांति के समय जब स्वतन्त्रा आन्दोलन की आग सम्पूर्ण देश में फैल गयी थी तब ग्रामीण लोगों का उससे अधूत रहना नामुकिन था 1857 की क्रान्ति जब अंग्रेज सरकार के विरूद्ध देश मे जो विद्रोह हुए उसमे ग्रामीण लोगा ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया उसमे मेरठ का नाम तो क्रांति धारा के नाम से जाना जाना गया। 1857 का स्वतन्त्रता संग्राम सभी जातियों, धर्म का समान योगदान रहा मेरठ के विक्टोरिया पार्क नामक जगह पर 10 मई 1857 को तीसरी अश्व सेना सवारो में अपने साथ 85 सैनिको को छुड़ाकर भारत की आजादी का विगुल फुका और ये वही सैनिक थे जिन्होंने 23 अप्रैल 1857 की कर्नल स्मिथ के दिये चर्वी लगे कारतूसो को चलाने से मना कर दिया था इसी प्रकार ग्रामीणों ने गाँधी के द्वारा चलाये गये विभिन्न आन्दोलनों मे (असहयोग आन्दोलन, स्वदेशी आन्दोलन, भारत छोड़ो आन्दोलन) मे भारी मौजूदगी दर्ज की और ग्रामीण राजनीति की शुरूआत की।

भारत के नागरिको को जन प्रतिनिधि चुनने व वोट देने चुनाव उम्मीदार बनने चुनावों मे हिस्सा लेने का राजनीतिक अधिकार प्राप्त है और आज ग्रामीण जनता भी अपने राजनीतिक अधिकारों की प्रति पूरी सजग है तो इस प्रकार भारतीय राजनीति में गाँव व ग्रामीणो की निर्णायक भूमिका है।

आज के समय राजनीतिक दल गाँव के लोगो के लिए ग्रामीण होने के और शक्ति के इन मूल स्रोतो पर अपना अधिकार जमाने के लिए प्रयासरत रहते है। भारत के विभिन्न दलों द्वारा गाँवों मै अपनी गुट बन्दी का लगातार प्रयास जारी रहता हे स्वतन्त्रता आन्दोलन में कांग्रेस की भूमिका से सभी ग्रामीण परिवेश परिचित होने के कारण कांग्रेस आजादी के उपरान्त लम्बे समय तक सत्ता पर काविज रही। आधुनिक समय में विभिन्न राजनीतिक दलों की सक्रियता व ग्रामीणों की जागरूकता से ग्रामीण विकास प्रक्रिया की कुछ गति मिली है।

लोकतन्त्र को तब तक सफल नही माना जा सकता है जब तक कि सत्ता और विकास के लाभ गाँवों तक नही पहुचाने अर्थात लोकतन्त्र में सत्ता का विक्रेन्दीकरण किया जाना नितान्त आवश्यक है जिससे अधिकाधिक जनता को सत्ता में भागादारी मिलाने को अवसर प्राप्त हो सके जिसे ''गासरूट डेमोंक्रेसी'' के नाम से सबोधित किया जाता है। इससे पंचायती राज संस्थाओं का स्वरूप और कार्यप्रणाली ही नही बदली बल्कि उनकी संरचना और कार्यकुशलता में भी

क्रांतिकारी परिवर्तन आ गया। यह कहना अतिशोक्ति नही होगी कि 73 वें संविधान के लागू हो जाने के बाद देश में सत्ता विकेन्द्रीकरण की दिशा में एक नये युग का सूत्रपात हो गया (22 दिसम्बर 1992 ई० लोकसभा 23 दिसम्बर ई० को राज्य सभी द्वारा पारित और 17 राज्यो के विधान मण्डलो द्वारा उसकी पुष्टि कर दिये जाने के बाद 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति ने इस विधेयक को अपनी स्वीकृति प्रदान की और 23 अप्रैल 1993 को लागू हो गया।

पंचायती राज आने से महिला राजनीतिक सशक्तिकरण का एक नया दौर शुरू हुआ और ग्रामीण महिलाओं में आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता व आत्मविश्वास को नये युग की शुरूआत हुई। यह सशक्तिकरण जमीनी स्तर पर हुआ है। ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण लागू होने से कुद राज्यों मे (बिहार, झारखण्ड, मध्यप्रदेश, उ०प०, कर्नाटक, केरल, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश, उडीसा) में एक नयी राजनीतिक संस्कृति की शुरूआत हुई।

देश के विभिन्न क्षेत्रों के गाँवों मे अन्य राजनीतिक दलों ने भरपूर प्रचार प्रसार किया। भारतीय जनता पार्टी भारतीय राष्ट्र को हिन्दू आदर्शो के रूप में विकसित करना चाहती है तो वही साम्यवादी दल देश से आर्थिक शोषण व पूंजीवाद को समाप्त करना चाहते है। हिन्दू महासभा और विश्व हिन्दू परिषद देश में हिन्दू राज्य स्थापना का लक्ष्य लिये हुए है ग्रामीणों में चुनाव प्रक्रिया मे निरन्तर बढ़ते योगदान के फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न राजनीतिक दलों का बेसिक लक्ष्य ग्रामीणों को काफी ज्ञान हो चुका है और वे अपने हितो के अनुसार दलगत राजनीतिक प्रसार मे भागीदार हो रहे है। ग्रामीण क्षेत्रो की अपनी एक राजनीतिक स्थिरता है जो गाँव के लोकल मुद्दो से प्रभावित रहती है। जिससे स्थानीय नेतागत शक्ति संघर्ष में अग्रसर होते हुए राजनीति करते है और गाँवों के स्थानीय मुद्दे विकास के साथ ज्वलन्त हो जाते है। गांव के नेता ग्राम पंचायत, ग्राम सभा में शक्ति प्रदर्शन निरन्तर जारी रखते है जिससे कुछ लोग तो ग्राम हित के कार्य करते है तथा कुछ दलगत आधार पर राजनीति में संघर्ष शील रहते है। गुटवादी का आधार जाति, समूह मिलता, राजनैतिक समानता, सामाजिक और आर्थिक समानता, हित समानता जैसे मुद्दो पर ग्रामीण राजनीतिक बोलवाला चलता है इसी प्रकार से ग्रामीण राजनीति में दलबन्दी अत्याधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ग्रामीण राजनीति में प्रत्येक जाति का अपना–अपना संगठन होता है इस प्रकार ठाकुर, ब्राह्मण, जाट, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व पिछड़ा वर्ग सभी मे जातिगत संगठनों राजनीतिक समानता दिखाई पड़ती है। जातिय समीकरणों और ग्रामीण संगठन के लक्ष्य के कारण भी ग्रामीण राजनीति एक व्यूह की भाँति हो जाती है इसमें किसान और जमीदारों के संगठन भी गाँव में पूर्णरूप से सक्रिय दिखाई पड़ते है जिसके पूर्ण प्रभाव पंचायती राज में राज्य सरकारों की कार्य प्रणाली पर भी पड़ता है।

उत्तर प्रदेश भारत का एक सबसे बड़ा व स्वतन्त्रता प्राप्ति से आज के देश को प्रधानमंत्री देने मे सबसे आगे रहने वाला राज्य है पं० नेहरू, शास्त्री जी, इंदिरा गाँधी, राजीव गाँधी, चौ० चरणसिंह, चन्दशेखर जीने उ०प्र० के लोकसभा क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व के चलते प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुँचने मे सफल रहे है किन्तु स्वतन्त्रा प्राप्ति के पश्चात् राज्य की स्थिति अराजकता की स्थिति जैसी प्रतीत हो रही है पिछले दषकों में राज्य की शासन की डोर जातिवादी शासको के

हाथ में रही है अतः भारतीय ग्रामीण राजनीति को समझने के लिए हमें उत्तर प्रदेश का उदाहरण प्रमुख हो सकता है।

उत्तर प्रदेश सर्वाधिक गाँवो वाला कृषि, धर्म सम्प्रदाय एक जातिगत राजनीति से ग्रहस्थ राज्य है जो केवल राज्य स्तर ही नही अपितु राष्ट्रीय राजनीति को भी पूर्ण रूप से प्रभावित करता रहा है उत्तर प्रदेश के ग्रामीण विकास के नाम पर विभिन्न राजनीति दल उभरे जिसका केवल एक ही उद्देश्य गाँवो की राजनीति को भुनाना है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस, भाजपा, सपा, बसपा व लोकदल की राजनीति देखी गयी है और ये दल यही से अपनी पहचान बनाने में सफल भी रहे है।

उत्तर प्रदेश में काग्रेस ने किसी खास वर्ग या जातिगत अपनी राजनीति भुनाने का प्रयास तो नही किया परन्तु अपने अस्तित्व स्वन्तत्रता आन्दोलन से भारत को आजाद कराने वाले राष्ट्रीय दल की पहचान बनाने में निस्तर सफल रही और निस्तर स्वाधीनता सघर्षो के आर्दशो पर चलने का दिखावा मात्र करती रही की वही केवल ग्रामीणों परिवेश को विकसित कर सकती है। उत्तर प्रदेश में किसान राजनीति और जाति आधारित राजनीति को कांग्रेस सम्भाल नही पायी और 13 मार्च 1992 को अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग की स्थापना के पश्चात भी कांग्रेस को इसका पूरा लाभ नहीं मिल पाया और दलितों के पूरा समूह भी कांग्रेस के हाथ से बहुजन समाजवाद पार्टी के पास चला गया और कृषि आधारित कोई सफल नीति नही होने से वह चौ० अजीत सिंह व मुलायम सिंह के पास पहुँच गया।

उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के विलोप होने से चौ० चरण सिंह की पहचान पिछड़े नेता के रूप में निखर कर आयी। उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्ग के लोगो, कृषक वर्ग जमींदार प्रथा की समाप्ती के कारण के एक मसीहा के रूप में उभरे जिसमें ग्रामीण परिवेश के ही जाट, अहीर, गुजर, लोधा राजपूत कुर्मी की अधिकता रही। चौ० चरण सिंह के एक उत्तराधिकारी उनके पुत्र अजीत सिंह की पहचान एक जाट नेता के रूप में उत्तर प्रदेश में उभरी उत्तर प्रदेश का कृषक वर्ग का, अजीत सिंह के प्रति भी खास लगाव रहा है। और चौ० चरण सिंह की भाँति वो एक सफल नेता तो नही बन पाये और उनके लोकदल को किसान वर्ग पार्टी हो कहा जाता रहा है और उत्तर प्रदेश में कृषक नेता के रूप में चौ० महेन्द्र सिंह टिकैत का नाम भी उल्लेखनीय है जो उत्तर प्रदेश के नये किसान आन्दोलनों का संचालन मे प्रमुखता से आगे रहे है वर्तमान मे चौ० अजीत सिंह ने हरित प्रदेश की मांग साथ मे अपना भविष्य खोज रहे है।

दूसरी तरफ दलित आन्दोलन के रूप में संगठित बहुजन समाज पार्टी दल दलितों क मसीहा डॉ० भीमराव अम्बड़ेकर के आदर्शो पर चलकर उनके सामाजिक समरता स्थापित करने के अधूरे सपनो को पूरा करने के नाम पर ग्रामीण राजनीति को पूर्ण रूप से प्रभाव मे लेने मे सफल रही मायावती के अनुयायी एक बात पर एक मत रहे है, कि मायावती के साथ उनका उज्ज्वल भविष्य की भूमिका निहित है मायावती काशीराम द्वारा गठित बहुजन समाज वादी दल एवं पिछड़ो की राजनीति का एकमात्र ऐसा दल है जो राष्ट्रीय स्तर पर अनी पहचान बनाने में सफल रहा है काशीराम के पश्चात् मायावती ही दल की सुप्रीमो है और उत्तर प्रदेश के दलितों का बहुत बड़ा

दल निवास करता है। इन्हीं दलितों के संगठित करके उन्हें बहुजन का नाम देकर काशीराम के सहयोग से मायावती मुख्यमंत्री बनने मे सफल रही और सोषल इन्जीनियरिंग के फामूले को राजनीति में लेकर आयी और अपने साथ न केवल दलित बल्कि सवर्णो को भी अपने साथ जोड़ा और मायावती ने मुसलमानों के पक्ष की बात करके उन्हें भाजपा के विरूद्ध करके अपनी ओर मिलाने का सफल प्रयास किया टिकट बटवारे के समय बहुजन समाज दल सदैव धर्म, सम्प्रदाय एवं जाति को ध्यान मे रखते हुए उम्मीदवार खड़े करता है। हालकि बहुजन समाज दल राष्ट्रीय दल है परन्तु यह उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त अन्य राज्यों मे अपना प्रभुत्व नही जमा पाया है। जिसका मुख्य कारण उत्तर प्रदेश के अधिकांश गाँवो मे जाति का प्रभाव होना अन्य राज्यों मे इस प्रभाव मे कमी होना माना जा सकता है।

भाजपा एक हिन्दूवादी दल है जो हिन्दूत्व की राजनीति करता है भाजपा को ब्राह्मण, बनियों, एवं स्वर्ण जातियों का प्रतिनित्व वाला दल भी कहा जाता है अर्थात भाजपा को ऐसा मानते है कि वह दलितो पिछड़ो की राजनीति नही करता है जिससे उसको उत्तर प्रदेश में दलित पूर्ण रूप से भाजपा की विचार धारा के साथ नही आ पाया भाजपा ने हमेशा धर्म की राजनीति को प्राथमिकता दी है जैसे रामजन्म भूमि मुद्दा सदैव वही भाजपा के सकारात्मक या नकारात्मकता के साथ परिणाम देता रहा है राष्ट्रीय स्थिति के साथ किसी भी स्थिति में उत्तर प्रदेश का मुसलमान भाजपा के साथ ही नही रहा है लेकिन राजनीति उठापटक के चलते भाजपा प्रदेश को मुख्यमंत्री देने मे सफल रही है।

उत्तर प्रदेश का सक्रिय दल समाजवादी पार्टी भी है जो राम मनोहर लोहिया के आदर्शो को साथ लेकर चल रहा है समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के मुसलमानों का भी नेतृत्व करते रहे है। उत्तर प्रदेश का अधिकांश मुसलमान के नेतृत्व में ही समाजवादी पार्टी से जुड़ा और मुलायम सिंह ने विभिन्न योजनाओं में मुसलमानों का लाभावित्त करते हुए एक साम्प्रदायिक राजनीति की भी शुरूआत की है।

निष्कर्ष

ग्रामीण राजनीति भारतीय राजनीति मे प्राण वायु का कार्य कर रही है और ये अपने प्रारम्भिक अवस्था मे भी ग्रामीण अपने (विशेषकर महिलाए भी) राजनीति अधिकारों के प्रति सजग हो चुके है भारतीय ग्रामीण मतदाता देश के विकास मे निर्णायक भूमिका का निवहन स्पष्ट रूप से कर रहा है। जिसका स्पष्ट उदाहरण हमें उत्तर प्रदेश की राजनीति में दिखाई पड़ता है। उत्तर प्रदेश में दलगत, जातिगत आधारित दलीय राजनीति सक्रिय होती दिखाई देती है। और ग्रामीण पूर्णरूप से सफल राजनीति योगदान दे रहे है।

सन्दर्भ सूची:

• *डॉ अवध नारायणदूवे : नयी पंचायत राज व्यवस्था*

• *शशि शर्मा– उत्तर प्रदेश के परिदृश्य में दलित राजनीति की भूमिका, शोध प्रबन्ध चौ० चरणसिंह विश्वविद्यालय –वर्ष 2002*

• बोस अजय–बहन जी, ए पालिटिकल बायोग्राफी ऑफ मायावती, पेगुइन बुक्स इण्डिया प्रा० लि०, 11 कम्यूनिटीसेन्टर पंचशील पार्क नई दिल्ली।

• तिवारी मनीष और पाण्डे रंजन– बैटल ग्राउण्ड यू०पी०, पालिटिक्स इन द लैन्ड ऑफ राम, टानक्यूवेर प्रेस 61, सिल्वर लाइन विल्डिग चेन्नई वर्ष 2013, पृष्ठ 230–233, 170–176

• श्री शरण – पंचायती राज और लोक तन्त्र